

>

Title: Need to accord necessary approval for the use of coal by thermal power units in Coal Blocks in Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के लोकसभा और राज्य सभा के सांसदों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इस मामले को लेकर गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह किया था। मैं एक ऐसा ही मामला सदन में उठाना चाहता हूँ।

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को जो दस कोल ब्लॉक्स अलाट किए थे, उनमें से सात कोल ब्लॉक्स मध्य प्रदेश में हैं और तीन छत्तीसगढ़ में हैं। मध्य प्रदेश द्वारा खनिज निगम के खनन के लिए संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी का चयन कर भारत सरकार के पास सभी आवश्यक अनुमतियों के लिए प्रेषित कर दिया है। मोरगा नम्बर-1 कोल ब्लॉक के लिए कोरबा का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी का चयन नहीं किया जा सका। शेष 9 ब्लॉक्स में से भारत सरकार ने तीन कोल ब्लॉक्स का कोल थर्मल पावर प्लांट के लिए उपयोग में लाने का निर्देश दिया है। इसमें भी एक कोल ब्लॉक जिसमें अभी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी है, इस ब्लॉक के अंतर्गत डोगरी ताल कोल ब्लॉक जिसके माइनिंग प्लान को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। शेष 6 कोल ब्लॉक में से तीन कोल ब्लॉक वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नो-गो एरिया में हैं, शेष तीन कोल ब्लॉक्स में कार्य प्रारंभ हेतु भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इन ब्लॉकों से जो कोयला निकलेगा, उसे स्टील एवं सीमेंट प्लांटों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने दस कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश को दे दिए हैं, यह तो यही कहावत हो गई- एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस लेना।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

श्री गणेश सिंह : मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जिन कोल ब्लॉक में कार्य प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है, उन्हें तत्काल अनुमति दें, तथा जिन ब्लॉकों में थर्मल पावरों को कोयला न देने का प्रतिबंध लगाया गया है, उन पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दें।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ लगातार जो भेदभाव हो रहा है, उस पर रोक लगायी जाए। किसानों की फसलों को पाले से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, पाले को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए एवं नई फसल बीमा योजना बनायी जाए। ...*

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

*(Interruptions) अँँ! **